



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 116-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 2, 2025 (ASADHA 11, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

खान तथा भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2025

**संख्या 02/01/2025-2IB-II.-** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 15 की उपधारा (1) और धारा 23 ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 62 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“62. तृतीय पक्ष के स्वामित्वाधीन भूमि पर खनन (1) जहां कोई खनिज रियायत किसी भूमि पर इन नियमों के अधीन दी गई है जिसके सम्बन्ध में लघु खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित हैं, भू-स्वामी के अधिकार खनिज को निकालने, खदान/खान में पहुंच, खनिजों का ढेर लगाने तथा समनुषंगी प्रयोजनों के लिए उस राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। भूमि स्वामी के ऐसे प्रयोग तथा ऐसी भूमि को हुई कोई हानि या क्षति के लिए न्यायोचित वार्षिक किराए तथा वार्षिक मुआवजे का हकदार है।

(2) खनिज रियायत धारक जिसे इन नियमों के अधीन खनिज रियायत दी गई है, खनिज को निकालने के लिए भूमि/क्षेत्र का प्रयोग करने का हकदार है जिसके सम्बन्ध में उक्त रियायत दी गई है। खनिज रियायत धारक

(क) रियायत के अधीन बंद किए गए भूमि क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्षिक किराया किन्तु जो संचालित नहीं की जा रही है, के लिए;

(ख) वास्तविक खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में स्वच्छ न्यायोचित वार्षिक किराया जमा वार्षिक मुआवजे का सम्पूर्ण कलेण्डर वर्ष के लिए और इसी प्रकार आगामी अनुवर्ती कलेण्डर वर्ष के लिए खनन संचालन के प्रारम्भ से पूर्व अग्रिम में भुगतान किए जाने के लिए, दायी होगा।

**व्याख्या.-** इस नियम के प्रयोजन के लिए, कलेण्डर वर्ष खनन संचालन के प्रारम्भ की तिथि से गिना जाएगा।

(3) यदि भू-स्वामी को उसकी सामान्य संक्रियाओं के लिए खनिज रियायत के साथ भूमि के भाग को प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो उस भाग के लिए कोई भी किराया तब तक अपेक्षित नहीं होगा, जब तक कि खनन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तथापि, यदि रियायत धारक भूमि को अवरुद्ध करता है या भूमि स्वामी को उसका उपयोग करने से रोकता है, तो सम्पूर्ण अवरुद्ध क्षेत्र के लिए किराए का भुगतान किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 63 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 “63. खनन के लिए प्रयुक्त भूमि हेतु किराए और मुआवजे का परस्पर समझौता.— वार्षिक किराए और वार्षिक मुआवजे की राशि भू-स्वामी तथा खनिज रियायत धारक के बीच परस्पर रूप से तय की जाएगी।”।
4. उक्त नियमों में, नियम 63क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 “63 क. सरकार द्वारा वार्षिक किराए और मुआवजे को नियतन.— यदि जहां भू-स्वामी और खनिज रियायत धारक के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से कोई करार नहीं होता है, तो सरकार इन नियमों के अधीन खनन के लिए खनिज रियायत पर दिए गए क्षेत्र के लिए भू-स्वामियों को खनिज रियायत धारकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वार्षिक किराए तथा वार्षिक मुआवजे की दर नियत तथा अधिसूचित कर सकती है:  
 परन्तु खनन पट्टा/संविदा के प्रारम्भ पर संबंधित खनिज रियायतकर्ता को तब तक खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा, जब तक कि वार्षिक किराया तथा वार्षिक मुआवजे की तय राशि, जैसी भी स्थिति हो, भूस्वामी को अग्रिम में भुगतान नहीं कर दी जाती:  
 परन्तु यह और कि सम्बन्धित खनिज रियायतकर्ता वार्षिक किराया तथा वार्षिक मुआवजे की तय राशि का, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम में भुगतान करेगा और अग्रिम में भुगतान करने में असफल रहने की दशा में, खनन संचालन निलम्बित किए जाने के लिए दायी होंगे।”।
5. उक्त नियमों में, नियम 64 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 “64. न्यायोचित बाजार किराए का अवधारण, यदि पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता नहीं किया है।  
 (1) जहां वार्षिक किराए की दर के सम्बन्ध में भू-स्वामी तथा खनिज रियायत धारक के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से कोई करार नहीं होता है, तो खनिज रियायत धारक ऐसी भूमि/क्षेत्र के सम्बन्ध में नियम 63क के अनुसार वार्षिक किराए के रूप में कलक्टर दर के दो प्रतिशत के बराबर राशि या ऐसी दर पर, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, का भुगतान करने का प्रस्ताव देगा।  
 (2) जहां भू स्वामी नियम 63 के अधीन परस्पर निपटान के लिए सहमत नहीं है तथा उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित वार्षिक किराए से भी संतुष्ट नहीं है, तो भू स्वामी या रियायत धारक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भुगतानयोग्य सामान्य न्यायोचित वार्षिक किराए के अवधारण के लिए जिला कलक्टर को संदर्भ करने के लिए सम्बद्ध जिले के कार्यभारी अधिकारी को आवेदन कर सकता है।  
 (3) जहां कोई भी पक्षकार उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन कलक्टर के संदर्भ को अधिमान देता है, तो सम्बद्ध जिले का कार्यभारी अधिकारी, ऐसा सन्दर्भ प्राप्त किए जाने के दस दिन के भीतर ऐसी भूमि के सम्बन्ध में न्यायोचित बाजार किराये के अवधारण के लिए कलक्टर को संदर्भ करने के लिए अग्रेषित करेगा। जिले का कार्यभारी खनन अधिकारी खनन रियायत धारक से कलक्टर के पास अनंतिम मुआवजे के रूप में उप-नियम (1) के अधीन यथाविहित एक वर्ष का किराया जमा करने की अपेक्षा करेगा। ऐसा करने पर खनिज रियायत धारक उक्त भूमि क्षेत्र पर खनन संक्रिया प्रारम्भ करने के लिए हकदार होगा।  
 (4) सम्बद्ध जिले के कार्यभारी खनन अधिकारी के संदर्भ पर, जिला कलक्टर इस नियम के उप-नियम (5) के अधीन यथा विहित पैरामीटरों पर अन्तर्विष्ट सूचना के साथ-साथ अपने दावे तथा प्रतिदावे के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को बुला सकता है तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दे सकता है।  
 (5) (क) संदर्भ के पक्षकारों को दी गई सुनवाई के अनुसरण में, जिला कलक्टर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए भूमि के न्यायोचित बाजार किराये का अवधारण करेगा:—  
 (i) भूमि की प्रकृति/स्वरूप अर्थात् कृषि योग्य (एकल फसल या बहुविध फसल) या बरानी या बंजर;  
 (ii) ऐसी भूमि जिसका प्रयोग खनिज रियायत देने से पूर्व तुरन्त किया गया था;  
 (iii) वार्षिक कुल आय जो भू स्वामी ऐसी भूमि प्रयोग से प्राप्त/अर्जित करने के योग्य था;  
 (iv) आमदन स्तर में सामान्य वृद्धि, जो मध्यवर्ती अवधि के दौरान ऐसी शुद्ध आय में घटित होगी ;  
 (v) इस प्रकार निकाली गई राशि को भूमि के अनिवार्य उपयोग के बदले में 30 प्रतिशत के बराबर राशि में जोड़ा जाएगा;  
 (ख) न्यायोचित बाजार किराये का अवधारण करते समय, जिला कलक्टर, ऐसी दर, जिस पर ऐसा वार्षिक किराया खनिज रियायत के चालू रहने के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ जाएगा, का भी निर्णय करेगा।  
 (ग) जिला कलक्टर सम्बद्ध खनन अधिकारी से उक्त संदर्भ की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर मामले का निर्णय करेगा।  
 (6) उपरोक्त उप-नियम (5) के अधीन न्यायोचित बाजार किराए के अवधारण के लिए विहित पैरामीटरों के होते हुए भी, कलक्टर उप-नियम (1) के अधीन यथा विहित या ऐसे क्षेत्र/भूमि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियत तथा अधिसूचित वार्षिक किराए, यदि कोई हो, की दर, जो भी उच्चतर हो, की राशि से कम वार्षिक किराए का अवधारण नहीं करेगा।

(7) जिला कलक्टर, समय-समय पर, उस द्वारा यथा अवधारित भू-स्वामी को ऐसे वार्षिक किराए का भुगतान करने के लिए पक्षकारों तथा खनिज रियायत धारकों को आदेश करेगा।

(8) जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सरकार के पास हो सकेगी।

(9) उप-नियम (1) के अधीन भुगतानयोग्य वार्षिक किराया तथा उप-नियम (3) के अधीन जमा किया जाने वाला वार्षिक अनंतिम किराया, अग्रिम में भुगतान किए जाने के लिए उचित समझा जाएगा, जिसमें विफल होने पर सम्बद्ध खनिज रियायतकर्ता द्वारा खनन संक्रियाओं का किया जाना निषिद्ध होगा।

(10) यदि खनिज रियायत धारक अपील दायर करता है, तो वह, इस प्रकार उसके खनन संक्रियाओं को प्रारम्भ करने या लगातार जारी रखने, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व अंतिम उपाय के रूप में सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि जमा करेगा, अपील प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन, जोकि आरंभिक निर्धारण की तिथि से सम्बन्धित होगा। यदि भू-स्वामी अपील दायर करता है, तो उसके बाद खनिज रियायत धारक भी अपील प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जोकि आरंभिक निर्धारण की तिथि से सम्बन्धित होगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 65 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"65. मुआवजे का अवधारण - (1) नियम 63 के अधीन पक्षकारों के बीच निर्धारित या नियम 64 के अधीन अवधारित तथा भुगतानयोग्य वार्षिक किराए के अतिरिक्त, भू-स्वामी वास्तविक खनन संक्रिया के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी भूमि को हुई किसी हानि के लिए न्यायोचित तथा युक्तियुक्त वार्षिक मुआवजे के भुगतान के लिए भी दायी होगा।

(2) उन मामलों में, जहां वार्षिक मुआवजे की राशि नियम 63 के अधीन पक्षकारों के बीच परस्पर रूप से निश्चित नहीं की गई है, तो वार्षिक मुआवजे की अनंतिम राशि, नदी तल खनन के मामले में कलक्टर दर की 0.5 प्रतिशत और/या सभी अन्य मामलों (नदी तल खनन को छोड़कर) में कलक्टर दर की एक प्रतिशत की राशि या वार्षिक मुआवजे की राशि की दर, जो नियम 63 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी उच्चतर हो, के बराबर होगी।

(3) जहां भूस्वामी या खनिज रियायत धारक उपरोक्त उप नियम (2) के अधीन विहित वार्षिक मुआवजे की राशि स्वीकृत करने के लिए सहमत नहीं है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि को हुई हानि या क्षति के सम्बन्ध में सामान्य तथा युक्तियुक्त वार्षिक मुआवजे के अवधारण के लिए जिला कलक्टर को खनन कार्यभारी अधिकारी के माध्यम से संदर्भ कर सकता है। किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे संदर्भ पर कलक्टर द्वारा निर्णय लम्बित करने पर, खनिज रियायत धारक उपरोक्त उप नियम (2) के अनुसार जिला कलक्टर के पास एक वर्ष के लिए अनंतिम वार्षिक मुआवजा जमा करेगा जहां इसके बाद रियायत धारक क्षेत्र का संचालन करने के लिए हकदार होगा:

परन्तु सन्दर्भ इसकी प्राप्ति के दस दिन के भीतर भेजा जाएगा।

(4) कार्यभारी अधिकारी के संदर्भ पर, जिला कलक्टर खनन संक्रियाओं के कारण ऐसी भूमि को होने वाली सम्भावित किसी हानि के कारण न्यायोचित वार्षिक मुआवजे की राशि का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा। कलक्टर दावे तथा तथा प्रतिदावे आमंत्रित करेगा तथा वार्षिक मुआवजे की राशि का अवधारण करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा।

(5) (क) कलक्टर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि को हुई हानि या क्षति के लिए न्यायोचित वार्षिक मुआवजा अवधारित करेगा:-

- (i) भूमि की प्रकृति या स्वरूप अर्थात् कृषि योग्य (एक फसल या बहु फसल) या बाराणी या बंजर;
- (ii) आर्थिक गतिविधि, जिसके लिए ऐसी भूमि खनिज रियायत देने से तुरन्त पूर्व प्रयोग की जा रही थी;
- (iii) की गई हानि की प्रकृति तथा सीमा तथा जैसा कि क्या ऐसी भूमि खनन संक्रिया के समापन के बाद पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुधारयोग्य है या हानि अनपलट है;
- (iv) आर्थिक गतिविधि, जिसके लिए ऐसी भूमि किसी निवेश सहित या के बिना खान समापन के बाद प्रयोग की जा सकती है, तथा विवरणी की किस्म ऐसे पुनःस्थापना के बाद अनुवर्ती के योग्य है;
- (v) भूस्वामी द्वारा इसके सम्भावित प्रयोग के लिए खान समापन नक्शे के अनुसार भूमि के पुनःस्थापन या सुधार या पुनर्वास के लिए खनिज रियायत धारक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों तथा प्रस्तावित खर्च का विस्तार।

(ख) वार्षिक मुआवजे की राशि अवधारित करते समय कलक्टर रियायत अवधि के लिए भूस्वामी को भुगतानयोग्य कुल अनुमानित वार्षिक मुआवजे की राशि को ध्यान में रखेगा। यदि किराए की कुल राशि तथा निर्धारित वार्षिक मुआवजे की राशि, भूमि के वर्तमान बाजार दर से अधिक है, तो खनिज रियायत धारक भूस्वामी के उसके लिए सहमत होने के अध्यक्षीन ऐसी दरों पर भूमि खरीदने के लिए विकल्प दे सकता है। दूसरी ओर, कलक्टर, यह ध्यान में रखते हुए कि भूस्वामी खनन संक्रिया के समापन के बाद भूमि का स्वामित्व निरन्तर रखेगा, वार्षिक मुआवजे की राशि अवधारित कर सकता है;

- (ग) यदि खनिज रियायत धारक वास्तविक खनन सक्रिया के लिए अपेक्षित भूमि के भाग के सम्बन्ध में परस्पर वार्षिक मुआवज़ा निर्धारित करने के योग्य है, तो भूमि के ऐसे भाग के लिए वार्षिक मुआवज़ा समझौते के अध्यक्ष नहीं होगा। तथापि, संचालन क्षेत्र के भाग के सम्बन्ध में पहले निर्धारित वार्षिक मुआवज़े की राशि को विवादित क्षेत्र के लिए वार्षिक मुआवज़ा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- (6) जहां कलक्टर द्वारा अवधारित अंतिम मुआवज़े की राशि उप-नियम (2) के अनुसार पहले ही जमा वार्षिक मुआवज़े की अनुमानित राशि से अधिक निकाली जाती है, तो खनिज रियायत धारक, कलक्टर द्वारा मांग करने पर पन्द्रह दिन के भीतर वार्षिक मुआवज़े की अंतिम राशि तुरन्त जमा करवाएगा:
- परन्तु यदि अन्तिम वार्षिक मुआवज़े की राशि संविदाकार/पट्टाधारी द्वारा पहले ही जमा राशि से कम रह जाती है, तो अतिरिक्त राशि पंद्रह दिन के भीतर उसे वापिस की जाएगी:
- परन्तु यह और कि यह कार्यवाही सन्दर्भ की प्राप्ति की तिथि से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी। ऐसा करने में विफल रहने पर, कलक्टर दर की 2.5 प्रतिशत और/या सभी अन्य मामलों (नदी तल खनन को छोड़कर) में कलक्टर दर के 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक मुआवज़े का भू-स्वामी को भुगतान करना पट्टेदार या संविदाकर्ता के स्वतः दायित्व के परिणामिक होगा।
- (7) कलक्टर द्वारा अवधारित वार्षिक मुआवज़े की राशि के आदेश अन्तिम तथा पक्षकारों पर बाध्य होंगे तथा खनिज रियायत धारक, खनिज रियायत के प्रचलन के दौरान वार्षिक रूप से भू-स्वामी को ऐसे वार्षिक मुआवज़े की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
- (8) कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील सरकार को की जा सकेगी।
7. उक्त नियमों में, नियम 98 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “98क. अन्तर्राज्यीय पारगमन पास.—(1) खनन पट्टा/संविदा/परमिट अथवा पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी वाहक के माध्यम से खनिजों का कोई भी प्रेषण, ई-पारगमन पास/पारगमन पास (दोहरी प्रति में), जैसी भी स्थिति हो, के साथ होगा। वाहक का प्रभारी अधिकारी प्रयोजन हेतु चेक पोस्ट पर अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर पारगमन पास प्रस्तुत करेगा।
- (2) खनिज ले जाने वाले सभी वाहकों को चेक पोस्ट पर रुकना होगा और संबंधित चेक पोस्ट द्वारा क्लीयरेंस प्राप्त करने के उपरांत ही आगे बढ़ना होगा। चेक पोस्ट का प्रभारी ई-पारगमन पास/पारगमन पास, जैसी भी स्थिति हो, की पहली प्रति पर आवश्यक प्रविष्टि करेगा और उसे ऐसे वाहक के संचालक को वापस देगा और ऐसे ई-पारगमन पास/पारगमन पास की दूसरी प्रति चेक पोस्ट के अभिलेख में रखी जाएगी।
- (3) विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उठाए गए खनिजों के परिवहन और भण्डारण और पट्टाधारित क्षेत्रों और डिपो से खनिजों के परिवहन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने हेतु, सरकार राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर, अवरोधक (अवरोधकों) और धर्म-काँटा (धर्म-काँटों) के साथ या के बिना चेक पोस्ट की स्थापना कर सकती है।
- (4) तालिका में दर्शाए अनुसार अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित अधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भी स्थान पर किसी वाहन को रोक सकता है और जांच कर सकता है और वाहन का कार्यभारी व्यक्ति मांग करने पर वैध पारगमन पास/परमिट और अन्य विवरण जैसे बिल (बिलों) या रसीद (रसीदों) या परिदान पत्र (पत्रों) को प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
I	निदेशक, खान तथा भू-विज्ञान अथवा इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
II	राज्य खनन अभियंता	सम्पूर्ण राज्य
III	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	अपने-अपने जिलों के भीतर
IV	खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता	अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर
V	जिला खनन अधिकारी	संबंधित जिला
VI	पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो	अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर

(5) प्रत्येक खनन पट्टा अथवा/या अनुज्ञप्ति धारक खनिजों के स्टॉक और लेखों और उससे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण, सत्यापन और जांच तथा नमूने लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और पारगमन के दौरान वाहन की जांच और निरीक्षण करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी के साथ समन्वय करेगा।

(6) प्रत्येक खनन पट्टा/संविदा/परमिट धारक तथा अन्य खनिज अनुज्ञप्तिधारी तीहरी प्रति में ई-पारगमन पास/पारगमन पास जनित करेगा तथा ई-पारगमन पास/पारगमन पास की दूसरी (दोहरी प्रति) तथा तीसरी (तिहरी प्रति) सौंपेगा तथा मूल प्रति पुस्तक में रखेगा।

(7) खनिज का प्रयोग करने वाले पट्टेदारों और स्क्रीनिंग संयंत्र के स्वामी को उसकी अपनी लागत पर उसका अपना धर्म-काँटा रखने के लिए कहा जा सकता है तथा वाहक को धर्म-काँटे की तोल पची के साथ पारगमन पास जारी करेंगे। प्रत्येक खनन पट्टा/संविदा और अन्य खनन अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाहकों को ई-पारगमन पास/पारगमन पास की दो प्रतियां – एक दोहरी (दूसरी प्रति) तथा एक तिहरी (तीसरी प्रति) ले जानी होगी। चैक पोस्ट और धर्म-काँटे पर लगाया गया अमला, परिवहन किए जाने वाले खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वाहक केवल वाहन प्रभारी द्वारा रखी गई तिहरी प्रति पर आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद चैक पोस्ट स्टाफ से क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद ही प्रस्थान करेगा तथा कार्यालय अभिलेख के लिए प्रतिलिपि प्राप्त करेगा।

(8) धर्म-काँटे का स्वामी धर्म-काँटे को उचित कार्यशील स्थिति में रखेगा तथा किसी भी प्रकार की खराबी अथवा तकनीकी गड़बड़ी संबद्ध खनन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(9) बैरियर अथवा धर्म-काँटे सहित या के बिना प्रत्येक चैक पोस्ट के कार्य घण्टे खनन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अग्रिम में घोषित किए जाएंगे तथा खनिज परिवहन की साधारण अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(10) चैक पोस्ट तथा/या धर्म-काँटे का प्रभारी सरकारी अमला वहन ले जाए जा रहे खनिज की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन करेगा तथा पारगमन पास/परमिट की एक प्रति वापिस करेगा। वह तथा ले जाए जा रहे खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता के बीच भिन्नता से सम्बन्धित कोई टिप्पणी पास/परमिट की दोनों प्रतियों में रिकॉर्ड करेगा तथा उसे पास/परमिट में दर्शाएगा और उसे खनन अधिकारी के ध्यान में लाएगा।

(11) वाहन का प्रभारी व्यक्ति, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए भेजने वाले, पाने वाले तथा खनिजों के बारे में सभी सम्बन्धित सूचना देगा।

(12) खनिज तथा वाहन की जांच करने के बाद चैक-पोस्ट या धर्म-काँटे का प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी पारगमन पास पर तिथि तथा समय सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा पदनाम लिखेगा।

(13) यदि प्रभारी अधिकारी या चैक-पोस्ट का अमला या धर्म-काँटा अमला के पास विश्वास करने का यह कारण है कि खनिज पारगमन पास/परमिट द्वारा कवर्ड नहीं है या परिवहन वैध परमिट/पास के बिना है, तो ऐसा अधिकारी वाहन को रोकेगा तब चैक-पोस्ट या धर्म-काँटे का प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी खनिज के परिवहन में प्रयुक्त खनिज (खनिजों), वाहन (वाहनों), औजार (औजारों), उपकरण (उपकरणों) या कोई अन्य वस्तु (वस्तुओं) को जब्त करेगा। जब्त खनिज (खनिजों), वाहन (वाहनों), औजार (औजारों), उपकरण (उपकरणों) या किसी अन्य वस्तु (वस्तुओं) अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश से जब्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(14) हरियाणा में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों से लदे वाहनों पर फीस, प्रति मीट्रिक टन एक सौ रूपए होगी, यदि ई-पारगमन में गंतव्य हरियाणा के भीतर किसी भी स्थान पर दर्ज किया गया है और यदि ई-पारगमन में गंतव्य, हरियाणा से बाहर किसी अन्य स्थान पर दर्ज किया गया है, तो प्रति मीट्रिक टन फीस बीस रूपए होगी।

#### 8. उक्त नियमों में, प्रथम अनुसूची में,—

(i.) क्रम संख्या 1, इसके अधीन मदों तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"1	पत्थर, गोला पत्थर तथा बजरी	100";
----	----------------------------	-------

(ii) क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"2	चूना पत्थर तथा चूना कंकर	150";
----	--------------------------	-------

(ii) क्रम संख्या 10, इसके अधीन मदों और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या, इसके अधीन मदें तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"10	गैर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त साधारण बालू	
(i)	सिलिका बालू से संबद्ध साधारण बालू	150
(ii)	कछारी कार्रवाई के कारण जमा किया गया सामान्य बालू	80"।

टी० एल० सत्यप्रकाश,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT**

**Notification**

The 2nd July, 2025

**No. 02/01/2025-2IB-II.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 and section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules (Amendment) Rules, 2025.
2. In the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals & Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), for rule 62, the following rule shall be substituted, namely:-

**“62. Mining over land in the ownership of third parties.-**

(1) Where a mineral concession is granted under these rules over any land in respect of which minor mineral rights vest in the State Government, the rights of the landowner shall be subordinate to that of the State Government for extraction of the mineral, access to the quarry/mine, stacking of minerals and other subsidiary purposes. The landowner is entitled to a fair annual rent and annual compensation for such use of the land and any damage or injury caused to such land.

(2) A mineral concession holder, who is granted the mineral concession under these rules, is entitled to use the land/ area for extraction of mineral in respect of which the said concession is granted. The mineral concession holder shall be liable to pay, - (a) the annual rent in respect of the land area blocked under the concession but not being operated; and

(b) the fair annual rent plus annual compensation in respect of the area used for actual mining operations shall paid in advance before commencement of mining operation for full calendar year and similarly for next consecutive year.

**Explanation:-** For the purpose of this rule, calendar year will be counted from the date of commencement of mining operation.

(3) If a landowner is allowed to continue using part of the land for their usual activities alongside a mineral concession, no rent is required for that portion as long as it is not used for mining. However, if the concession holder blocks the land, preventing the landowner from using it, rent must be paid for the entire blocked area.”.

3. **In the said rules, for rule 63, the following rule shall be substituted, namely:-**

**“63. Mutual settlement of rent and compensation for the land use for mining.-** The amount of annual rent and the annual compensation shall be settled mutually between the landowner and the mineral concession holder.”.

4. **In the said rules, for rule 63A, the following rule shall be substituted, namely:-**

**“63A. Fixation of annual rent and compensation by Government.-** In case where no agreement is reached by way of mutual settlement between land owner and mineral concession holder, the Government may fix and notify the rate of annual rent and annual compensation, to be paid by the mineral concession holders to the landowners for area granted on mineral concession for mining under these rules:

Provided that on commencement of the mining lease/contract, the mineral concessionaire concerned, shall not be permitted to commence the mining activity unless the settled amount of annual rent, and, annual compensation, as the case may be, is paid in advance to the land owner:

Provided further that the mineral concessionaire concerned, shall pay the annual rent, and, annual compensation, as the case may be, in advance before the starting of each consecutive year, and, in the event of failure to make the advance payment, the mining operations shall be liable to be suspended.”.

5. **In the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely:-**

**“64. Determination of fair market rent, if not mutually settled between the parties.-**

(1) Where no agreement is reached by way of mutual settlement between the landowner and the mineral concession holder regarding the rate of annual rent, the mineral concession holder shall offer to pay an amount equal two percent of the collector rate or at such rate as may be notified by the Government as per rule 63 A in respect of such land/area, whichever is higher, as rent

- (2) Where the land owner is not agreeable for a mutual settlement under rule 63 and is also not satisfied with the annual rent offered to be paid under sub-rule (1) above, the landowner or the concession holder may apply to the officer-in-charge of the concerned district to make a reference to the District Collector for determination of the fair annual rent payable in respect of such land.
- (3) Where either of the parties prefer a reference to the District Collector under sub-rule (2) above, the officer-in-charge of the concerned district shall forward the reference to the District Collector for determination of the fair market rent in respect of such land within 10 days of receiving such reference. The mining officer-in-charge of the district shall also require the mineral concession holder to deposit the rent for one year as prescribed under sub-rule (1) above as a tentative annual rent with the Collector. Upon so doing, the mineral concession holder shall be entitled to commence mining operations over the said land area.
- (4) Upon a reference from the mining officer-in-charge of the district concerned, the District Collector may call upon the parties to furnish the details of their claims and counter claims, inter alia, containing information on the parameters prescribed under sub-rule (5) of this rule and afford an opportunity of hearing to the parties.
- (5) (a) Pursuant to the hearing granted to the parties to the reference, the District Collector shall determine the fair market rent of the land keeping in view the following:
- (i) nature/ character of the land i.e. arable (single crop or multiple crop) or barani or banjar;
  - (ii) use to which such land was being put immediately before the grant of mineral concession;
  - (iii) annual net income that the landowner was able to derive/ earn from such land use;
  - (iv) normal increase in the income level that would have taken place in such net income during the intervening period;
  - (v) amount so worked out shall be added an amount equal to thirty percent in lieu of compulsory use of the land;
- (b) While determining the fair market rent, the District Collector shall also decide the rate at which such annual rent shall be increased on year-to-year basis during the currency of the mineral concession.
- (c) The District collector shall decide the same within forty-five days of receiving of said reference from mining officer concerned.
- (6) Notwithstanding the parameters prescribed for determining the fair market rent under sub-rule (5) above, Collector shall not determine the annual rent at a rate lesser than the amount as prescribed under sub-rule (1) or rate of annual rent fixed and notified, if any, by the government in respect of such area/land whichever is higher.
- (7) The District Collector shall order parties and the mineral concession holder to pay such annual rent to the landowner from time to time, as determined by him.
- (8) Any appeal against the order of the District Collector shall lie with the Government.
- (9) The annual rent payable under sub-rule (1), and, the annual tentative rent to be deposited under sub-rule (3), may be deemed fit to be paid in advance, failing which the undertakings of mining operations, by the mineral concessionaire concerned, shall be forbidden.
- (10) In case the mineral concession holder files an appeal, he shall deposit the amount determined by the authority concerned, thus before his commencing the mining operations or his/its continuing with mining operations, as the case may be, as an interim measure, subject to the final decision of the appellate authority, which will relate back to the date of initial determination. In case the land owner files an appeal, thereupon also the mineral concession holder shall be liable to pay the amount determined by the authority concerned, subject to final decision of the appellate authority, which will relate back to the date of initial determination

**6. In the said rules, for rule 65, the following rule shall be substituted, namely:-**

**“65. Determination of compensation.-** (1) In addition to the annual rent settled between the parties under rule 63 or determined and payable under rule 64, the landowner shall also be entitled to payment of a fair and reasonable annual compensation for any damage caused to such land in respect of the area under actual mining operations.

(2) In cases where the amount of annual compensation is not mutually settled between the parties under rule 63, the tentative amount of annual compensation shall be equal to an amount 0.5% of the collector rate in case of riverbed mining and/or 1% of collector rate in all other cases (except riverbed mining) or at the rate of an amount of annual compensation, as notified by the Government under rule 63 A, whichever is higher.

(3) Where the landowner or the mineral concession holder is not agreeable to accept the amount of annual compensation prescribed under sub-rule (2) above, either of them may seek a reference through mining officer-in-charge to the District Collector for determination of fair and reasonable annual compensation with reference to the damage or injury caused to such land. Pending a decision by the District Collector on such reference by either of the parties, the mineral concession holder shall deposit the tentative annual compensation amount for one year with the District Collector in accordance with sub-rule (2) above, after which the concession holder shall be entitled to operate the area:

Provided that the reference, shall be forwarded within ten days of the receipt of the same.

(4) Upon a reference from the officer-in-charge, of the district concerned, the District Collector shall proceed to determine the fair annual compensation amount on account of any damage likely to be caused to such land on account of the mining operations. The Collector shall invite claims and counter claims and afford an opportunity of hearing to the parties before determining the annual compensation amount.

(5) (a) The Collector shall determine the fair annual compensation for the damage or injury caused to such land keeping in view the following, namely:-

- (i) nature or character of the land i.e. arable (single crop or multiple crop) or barani or banjar;
- (ii) economic activity for which such land was being used immediately before the grant of mineral concession;
- (iii) nature and extent of damage caused and as to whether such land is fully or partially reclaimable after closure of the mining operations or the damage is irreversible;
- (iv) economic activity for which such land may be used after mine closure, with or without any investment, and the kind of returns it is capable of yielding after such restoration.
- (v) extent of efforts and expenditure proposed to be made by the mineral concession holder for restoration or reclamation or rehabilitation of the land as per the mine closure plan for its eventual use by the landowner;

(b) While determining the annual compensation amount, the Collector shall keep in view the total annual rent and the estimated annual compensation amount payable to the landowner throughout the concession period. In case the sum total of the annual rent and the annual compensation amount assessed is more than the prevailing market value of land, the mineral concession holder may be given an option to buy the land at such rates subject to the landowner agreeing to the same. Alternatively, the Collector may determine the annual compensation amount keeping in view that the landowner would continue to retain the ownership of land after the closure of mining operations.

(c) In case the mineral concession holder and the landowner(s) are able to settle the annual compensation mutually in respect of a portion of the land required for actual mining operations, compensation for such portion of the land shall not be a subject for settlement. However, the amount of annual compensation already settled in respect of part of the operating area shall be kept in view while settling the annual compensation for the disputed area.

(6) Where the amount of final annual compensation determined by the collector works out to be more than the tentative amount of annual compensation already deposited as per sub-rule (2), the mineral concession holder shall deposit immediately on demand by the Collector, the additional amount of annual Compensation within fifteen days:

Provided that in case the amount of final annual compensation works out to be less than the amount already deposited by the contractor/lessee, the excess amount shall be refunded to him within fifteen days:

Provided further that this exercise shall be completed within a period of forty-five days from the date of receipt of reference. Failure to do so shall result in the automatic liability of the lessee or contractor to pay to the landowner an annual compensation shall be equal to an amount 2.5% of the collector rate in case of riverbed mining and/or 5% of collector rate in all other cases (except riverbed mining).

(7) The annual compensation amount determined by the District Collector shall be final and binding on the parties and the mineral concession holder shall be liable to pay such annual compensation amount to the landowner annually during the currency of the mineral concession.



(8) An appeal against the order of the Collector shall lie with the Government”.

**7. In the said rules, after rule 98, the following rule shall be inserted, namely:-**

**“98A. Interstate Transit Pass.-** (1) All dispatch of minerals by holder of mining lease/contract/permit or prospecting licence by a carrier shall be accompanied with an e-transit pass/transit pass as the case may be, in duplicate. The person in-charge of the carrier shall produce the transit pass at the check post for the purpose, or on demand by an officer, authorized by the State Government.

(2) All carriers, carrying the mineral shall stop at the check post and proceed after having been cleared by the respective check post. The in-charge of the check post shall make necessary endorsement on the first copy of the e-transit pass/transit pass as the case may be, and return to the Operator of such carrier and second copy of such e-transit pass/transit pass shall be kept in records of the check post.

(3) With a view to check the transport and storage of minerals raised without lawful authority and to check the quality and quantity of minerals transported from lease-hold areas and depot, the Government may set up check-post(s) with or without barrier(s) and weigh-bridge(s) at any place within the State.

(4) The following officers within their respective jurisdiction as shown in the Table, may stop and check any carrier at any place within their respective jurisdiction and the person in-charge of the carrier shall furnish the valid transit pass/permit and other particulars such as bill(s) or receipt(s) or delivery note(s) on demand, namely:-

**Table**

	<b>Designation of the Officer</b>	<b>Jurisdiction</b>
I.	Director, Mines and Geology or any officers as authorized by him in this behalf	Whole of the State
II.	State Mining Engineer	Whole of the State
III	District Magistrate/Assistant District Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate	Within their respective Districts.
IV.	Mining Engineer/ Assistant Mining Engineer	Within their respective Jurisdiction.
V.	District Mining Officer	District concerned.
VI.	Police Officer not below the rank of Sub-Inspector	Within their respective Jurisdiction.

(5) Every holder of mining lease and/or license shall provide necessary assistance to the authorized officer to inspect, verify and check the stocks and accounts of minerals and any other documents pertaining thereto and draw samples and shall co-operate with the concerned authority for checking and inspection of the carrier during transit.

(6) Every holder of a mining Lease/contract/permit and other mineral licensee shall generate e-transit pass/transit Pass in triplicate Form and shall handover duplicate (2nd copy) and triplicate (3rd copy) of the e-transit pass/ transit pass to the in-charge of the carrier and shall keep the original copy in the book.

(7) The lessee or the owner of the screening plant using the mineral may be asked to have their own weighbridge at their own cost and shall issue transit pass along with weighment slip of the weighbridge to the carrier. Every holder of mining lease/ contract/ permit and other mineral licensee shall ensure that all carriers shall carry two copies of the e-transit pass/transit pass – one duplicate (2nd copy) and one triplicate (3rd copy). The staff deployed at check posts and weighbridge shall verify the quality and quantity of mineral being transported and ensure that the carrier shall proceed only after being cleared by the check post after making necessary endorsements on the triplicate copy held by the carrier in-charge and shall receive the duplicate copy for office records.

(8) The owner of the weigh-bridge shall keep the weighbridge in perfect working condition and any break down or malfunctioning shall be reported forthwith to the concerned mining officer.

(9) The working hours of each check-post, with or without barrier or weighbridge shall be announced in advance by the Mining Officer, as the case may be, and shall commensurate with general requirement of the mineral traffic.

(10) The checking staff in-charge of check-post and/or weigh-bridge may verify the quantity and quality of the mineral carried and shall return one copy of the transit pass/permit. He may record in both copies of the

pass/permit any observation relating to the discrepancy between the quantity and quality of mineral carried and that shown in the pass/permit and shall bring the same to the notice of the Mining Officer.

(11) The person in-charge of the carrier shall, if so required by the authorized officer, furnish all relevant information regarding consigner, consignee and minerals.

(12) After checking the mineral carrier, the officer in-charge of the check-post or weigh-bridge or any other authorized officer shall put his signature and designation with date and time on the transit pass.

(13) If the officer in-charge or staff of check-post or weigh-bridge has reasons to believe that the mineral is not covered by the transit pass/permit or the transportation is without a valid permit/pass, such officer shall detain the vehicle. Then the officer in-charge of check-post or weigh-bridge or any other authorized officer shall seize the mineral(s), vehicle(s), tool(s), equipment(s) or any other thing(s) used in transport of minerals. The seized mineral(s), vehicle(s), tool(s), equipment(s) or any other thing(s) shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence and shall be disposed of in accordance with the direction of the Court.

(14) The fee on a vehicle loaded with minor minerals coming from other States into Haryana shall be one hundred rupees per metric tonne, if the destination in e-transit is entered at any place within Haryana, and if the destination in e-transit is entered at any place outside Haryana, then it shall be twenty rupees per metric tonne.

**8. In the said rules, in First Schedule, -**

(I) for serial number 1, items thereunder and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:-

“1	Stone and Boulder Gravel	100”;
----	--------------------------	-------

(II) for serial number 2, and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:-

“2	Lime Stone and Lime Kankar	150”;
----	----------------------------	-------

(III) for serial number 10, items thereunder and entries there against, the following serial number, items thereunder and entries there against shall be substituted, namely:-

“10.	Ordinary sand used for non-industrial purposes-	
(i)	Ordinary sand associated with silica sand	150
(ii)	Ordinary sand deposited due to alluvial action	80”.

T. L. SATYAPRAKASH,  
Commissioner & Secretary to Government Haryana,  
Mines and Geology Department.